लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5371

जिसका उत्तर बुधवार, 05 अप्रैल, 2023 को दिया जाएगा

प्याज और आलू की कीमतों में गिरावट

5371. श्री कुलदीप राय शर्मा:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में अच्छी फसल होने के कारण घरेलू बाजार में प्याज और आलू की कीमतों में भारी गिरावट आई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं कि प्याज और आलू के किसानों को उनकी उपज का इष्टतम मूल्य मिले;
(ग) क्या सरकार ने देश में प्याज और आलू के किसानों को हुई हानि का आकलन किया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार का प्याज और आलू के किसानों को इस संकट से निकालने के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है; और
(च) क्या देश में भंडारण की अपर्याप्त और अनुपयुक्त सुविधाएं तथा देश में गोदामों की संख्या में कमी किसानों की पीड़ा का एक प्रमुख कारण है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ङ): देश के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में प्याज और आलू की मंडी कीमतों में गिरावट आई है। खरीफ और लेट खरीफ फसलों की थोक आवक, जो भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं हैं, के कारण प्याज की कीमतों में गिरावट आई है। इसी तरह आलू के अच्छे उत्पादन और बाजार में भारी आवक के कारण मंडी कीमतों में गिरावट आई है। किसानों का समर्थन करने के लिए, सरकार ने नेफेड़ और एनसीसीएफ को प्रमुख उत्पादक राज्यों के बाहर खपत केंद्रों में एक साथ निपटान के लिए प्याज खरीदने का निर्देश दिया है। दिनांक 29.03.2023 तक दोनों एजेंसियों ने कुल 26,602.26 मीट्रिक टन की खरीद की है। सरकार ने कम-फसली ऋतु के समय कीमतों को स्थिर करने के लिए अंशांकित और लक्षित रिलीज के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत रबी-2023 प्याज की 3.00 लाख मीट्रिक टन

खरीद और भंडारण करने का भी निर्णय लिया है। आलू के संबंध में, सरकार ने बाजार हस्तक्षेप स्कीम (एमआईएस) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 10.00 लाख मीट्रिक टन की खरीद को मंजूरी दी है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) नाम से एक छत्रक स्कीम लागू करता है, जिसके तहत उसने प्याज और आलू के लिए परिवहन और भंडारण सब्सिडी के लिए 35.32 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

केंद्र सरकार द्वारा किए गए उपायों के अलावा, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख प्याज और आलू उत्पादक राज्यों ने भी किसानों को समर्थन देने की घोषणा की है।

(च) पीएमकेएसवाई के तहत कोल्ड स्टोरेज/फ्रोजन स्टोर/सीए स्टोर/गोदाम सहित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय सामान्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत के 35% की दर से सहायता अनुदान प्रदान करता है और दुर्गम क्षेत्रों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, एफपीओ और एसएचजी की परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत के 50% की दर से सहायता अनुदान प्रदान करता है।

******